

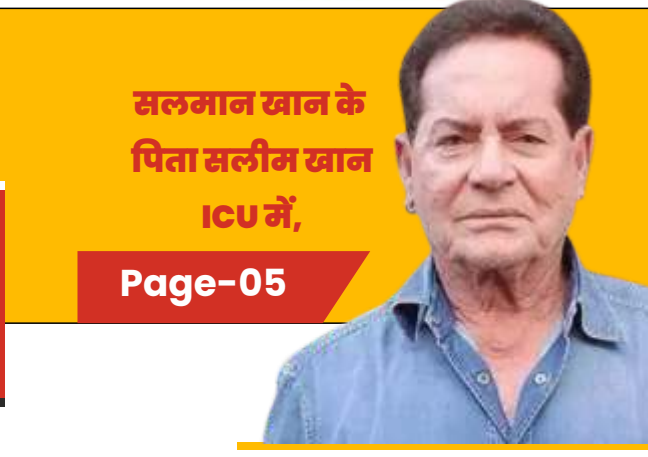


**प्रमोद भगत ने
छठा वर्ल्ड टाइटल
जीता**

Page-04



सच्ची खबर, सीधे आपके लिए



**सलमान खान के
पिता सलीम खान
ICU में,**

Page-05



खामेनेई का ट्रंप पर तीखा हमला

जिनेवा वार्ता के बीच तनाव और गहराया

अंतरराष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। कूटनीतिक बातचीत के इस अहम चरण के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा प्रहार किया है। उनके बयान के बाद दोनों देशों के बीच तलखी और बढ़ती नजर आ रही है। जिनेवा में हुई इस वार्ता को क्षेत्रीय स्थिरता और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा था। सूत्रों के अनुसार, बातचीत में प्रतिबंधों में संभावित राहत, परमाणु गतिविधियों पर निगरानी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि, वार्ता के समानांतर खामेनेई ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कई पोस्ट साझा कर अमेरिकी नेतृत्व पर निशाना साधा। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अक्सर दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति होने का दावा करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे ताकतवर सैन्य बल पर भी ऐसा हमला हो सकता है कि वह संभल न

सके। खामेनेई के इस बयान को सीधे तौर पर अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन और हालिया चेतावनियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। अमेरिकी प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल विकास और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। जवाब में तेहरान भी अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा की बात दोहरा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी वार्ता प्रक्रिया को जटिल बना सकती है। जहां एक ओर बंद कमरे में बातचीत जारी है, वहीं सार्वजनिक मंचों पर तीखे बयान अविश्वास को और गहरा कर रहे हैं। यूरोपीय देशों ने संयम बरतने और संवाद जारी रखने की अपील की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि क्या कूटनीतिक प्रयास किसी ठोस समझौते का रास्ता खोल पाएंगे। फिलहाल, दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं, लेकिन संवाद की निरंतरता को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। कूटनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि यदि आने वाले दौर की वार्ताओं में ठोस प्रगति नहीं हुई, तो क्षेत्रीय तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों का संकट और गहरा सकता है।

बड़ा उलटफेर! ऑस्ट्रेलिया हुआ बाहर,

जिम्बाब्वे ने मारी सुपर-8 में धमाकेदार एंट्री

खेल, टीवी भारतवर्ष

जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच टी20 विश्व कप में ग्रुप बी का मुकाबला बारिश के चलते हो गया है। ग्रुप-1 में भारत, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज हैं। वहीं, ग्रुप-2 में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका ने सुपर आठ में जगह बनाई है, जबकि एक स्थान के लिए टीम का क्वालिफाई करना शेष है। भारत का सुपर आठ में सामना दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज से होगा। पल्लेकल में बारिश के कारण जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच में टॉस भी नहीं हो सका और अंततः मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मौजूदा टी20 विश्व कप में सफर निराशाजनक रहा। एक तो टीम खिलाड़ियों की चोट की समस्या से जूझ रही थी और फिर उसे जिम्बाब्वे के खिलाफ उलटफेर का शिकार होना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के लिए असली मुश्किल तब हुई जब श्रीलंका ने भी टीम को हरा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 20 फरवरी को ओमान का सामना करना है। कंगारू टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सम्मान के साथ विश्व कप से विदा लेना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने से अब सुपर आठ की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। जिम्बाब्वे सातवीं टीम है जिसने अगले दौर में जगह बनाई है। अब सिर्फ एक स्थान के

लिए अमेरिका, नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच होड़ है। सुपर आठ में पहला ग्रुप भी तय हो गया है। ग्रुप-1 में भारत, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज हैं। वहीं, ग्रुप-2 में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका ने सुपर आठ में जगह बनाई है, जबकि एक स्थान के लिए टीम का क्वालिफाई करना शेष है। भारत का सुपर आठ में सामना दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज से होगा। पल्लेकल में रुक-रुककर लगातार बारिश होती रही जिस कारण पूरा मैदान कवर्स से ढका रहा। आउटफील्ड के चारों ओर कवर्स लगे रहे और कवर्स के ऊपर काफी पानी भरा हुआ था। मैच भारतीय समयानुसार तीन बजे से शुरू होना था, लेकिन इसमें टॉस भी नहीं हो सका। भारतीय समयानुसार शाम 6:10 बजे तक कटऑफ टाइम था, लेकिन मौसम की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ जिसके बाद दोनों कप्तानों से बात करने के बाद मैच को रद्द किया गया। सुपर-8 राउंड में प्रवेश के साथ ही जिम्बाब्वे के प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है। टीम अब अगले चरण में जीत की लय बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगी।



जेल से रिहा हुए अभिनेता

कर्ज विवाद केस में राजपाल यादव को मिली जमानत

मुंबई, टीवी भारतवर्ष

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को कर्ज विवाद से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत वह जेल से रिहा हो गए। इस फैसले से अभिनेता और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। मामला कथित रूप से आर्थिक लेन-देन और कर्ज चुकाने में देरी से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में अदालत ने पूर्व में सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। हालांकि, हालिया सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलीलों और प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करते हुए अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने

जमानत देते समय कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिनका पालन करना अभिनेता के लिए अनिवार्य होगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत अस्थायी है और मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। राजपाल यादव ने न्यायपालिका पर विश्वास जताया और कहा कि वह कानून का सम्मान करते हैं तथा पूरी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।



फडणवीस से मुलाकात

एनसीपी नेताओं ने की निष्पक्ष जांच की मांग

मुंबई, टीवी भारतवर्ष

राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई अहम मुलाकात के दौरान एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे भी सुनेत्रा पवार के साथ मौजूद रहे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हालिया घटना को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी चिंताएं रखीं। बैठक में दोनों नेताओं ने जोर देते हुए कहा कि संबंधित घटना की सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि जनता के बीच जो सवाल उठ रहे हैं, उनका स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। नेताओं का कहना था कि मामले को किसी भी तरह से दबाया नहीं जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि कानून के दायरे में रहते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, राज्य

सरकार इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कराने पर विचार कर रही है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में एनसीपी नेताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल सच को सामने लाना है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। फिलहाल, इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।



कांग्रेस का हमला:

हरदीप पुरी और एपस्टीन के कथित संबंधों पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली, टीवी भारतवर्ष

कॉरपोरेट गवर्नेंस और नीतिगत पारदर्शिता के मुद्दे पर राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी फाइनेंसर तथा यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के बीच कथित संबंधों को लेकर मंगलवार को गंभीर आरोप लगाए। विपक्षी दल ने दावा किया कि 2014 से 2017 के बीच दोनों के बीच 62 ईमेल का आदान-प्रदान हुआ और 14 व्यक्तिगत मुलाकातें हुईं। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आंकड़ों को

सार्वजनिक करते हुए कहा कि "हरदीप पुरी ने 32 ईमेल भेजे जबकि एपस्टीन ने 30 ईमेल भेजे। जून 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद मुलाकातों का दौर शुरू हुआ, जो 2017 तक चला।" खेड़ा ने विशिष्ट तारीखों जैसे 5, 6, 8 और 9 जून 2014 को हुई बैठकों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इन दौरों में क्या चर्चा हुई थी और क्या सरकारी नीतियों की जानकारी साझा की गई। कांग्रेस ने यह भी सवाल किया कि जब हरदीप पुरी एक सामान्य नागरिक के रूप में मिल रहे थे, तो उन्होंने एपस्टीन के साथ सरकारी नीतियों का आदान-प्रदान क्यों किया। विपक्ष ने इस आधार पर मंत्री हरदीप सिंह पुरी के तत्काल इस्तीफे और मामले पर स्पष्ट स्पष्टीकरण की मांग की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला आगामी समय में मीडिया और संसद में बड़ी बहस का विषय बन सकता है। सत्तारूढ़ दल ने फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन भाजपा सूत्रों के अनुसार, मंत्री द्वारा सभी गतिविधियों का कानूनी और नीतिगत दायरे में किया जाना बताया गया है। मामले की गहन जांच और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस विवाद से भारत में सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के बीच संपर्क के नियमों और पारदर्शिता पर भी बहस छिड़ सकती है। इसके अलावा, यह मामला अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वित्तीय नेटवर्क से जुड़े संवेदनशील पहलुओं को भी उजागर कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जनता को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं, तो यह मुद्दा संसद और जनसुनवाई के जरिए और तीव्र रूप से उठाया जाएगा।



हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

TV

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1

प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़

ई-पेपर

विज्ञापन दर

सर्जिन	डिजिटल वर्क	संकायन	संकायन	संकायन	संकायन	संकायन	संकायन
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100,000

8601780000

पीएम मोदी ने मैक्रों से मुलाकात के बाद कहा, भारत-फ्रांस साझेदारी की कोई सीमा नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ मुलाकात की, जिसमें भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, व्यापार, जलवायु और संस्कृति में सहयोग पर जोर दिया। मैक्रॉन ने मुंबई की सैर और स्थानीय अनुभव की सराहना की।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसका उद्देश्य भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। यह वार्ता महाराष्ट्र लोक भवन में हुई, जहां दोनों नेताओं ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करते हुए आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक राष्ट्रपति मैक्रॉन की भारत की चौथी यात्रा के अंतर्गत हुई। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत की वित्तीय राजधानी में अपने अनुभव साझा किए और कहा कि मैक्रॉन को यह शहर पसंद आया और उन्होंने सुबह की दौड़ का आनंद लिया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, "मुंबई में अपने मित्र, राष्ट्रपति मैक्रॉन से मिलकर बहुत खुशी हुई! उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें यह शहर बहुत पसंद आया और उन्होंने सुबह की दौड़ का भी आनंद लिया!" दोनों नेताओं ने अपनी



वार्ता से पहले मुंबई के लोकसभा भवन में मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की। दोनों नेताओं को एक-दूसरे का अभिवादन करते हुए सौहार्दपूर्ण बातचीत करते देखा गया। आज सुबह मुंबई में सुबह की चहल-पहल शुरू होने के समय, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सुबह की सैर में शामिल होकर मुंबईवासियों को चौंका दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को फ्रांसीसी और भारतीय अधिकारियों सहित सुरक्षाकर्मियों के एक दल के साथ जॉगिंग करते देखा गया। यह जॉगिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और रास्ते में मीडिया और स्थानीय लोगों की ओर से कोई खास व्यवधान नहीं हुआ। उसी दिन, आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को दर्शाते हुए एक

मार्मिक क्षण में, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रॉन ने अपने आगमन पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस भाव ने कट्टरता और हिंसा के घावों का सामना कर चुके दो देशों के बीच एक सेतु का काम किया, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रॉन ने लचीलेपन और लोकतंत्र के उन साझा मूल्यों पर जोर दिया जो नई दिल्ली और पेरिस को आपस में जोड़ते हैं। वार्ता के दौरान, दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तारित करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए नए अवसरों का भी पता लगाया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार-

विमर्श किया, जिसमें सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दे मुख्य थे। दोनों नेताओं ने उच्चस्तरीय साझेदारी की पुष्टि करते हुए यह भी कहा कि भारत-फ्रांस सहयोग का कोई सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्रॉन के साथ मुलाकात में कहा कि भारत और फ्रांस के बीच संबंध स्थायी और गहरे हैं, और दोनों देश वैश्विक चुनौतियों के समाधान में मिलकर काम कर सकते हैं। इस अवसर पर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी फ्रांस की वैश्विक दृष्टि और सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

तारिक रहमान बने बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री, नई कैबिनेट में शामिल मंत्रियों की सूची

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

देश की राजनीतिक दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव के तहत, तारिक रहमान और सभी निर्वाचित बीएनपी सांसदों ने मंगलवार को ढाका स्थित राष्ट्रीय संसद भवन में शपथ ली। यह ऐतिहासिक समारोह 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनावों के बाद आयोजित किया गया, जिसमें बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान और उनके नवोदित मंत्रिमंडल को पद की शपथ दिलाई। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के 25 निर्वाचित सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली और 24 अन्य नवनिर्वाचित सांसदों ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। 13वें संसदीय चुनाव में रहमान की बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ने 297 में से 209 सीटें हासिल कीं, जबकि दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटें मिलीं। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने संसद के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सचिवालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 13वीं जातीय संसद (जेएस) के सभी 297 नवनिर्वाचित सांसदों ने पहले संसद सदस्य (सांसद) के रूप में और फिर संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। बीएनपी ने संसदीय दल के नेता के चुनाव के लिए सुबह 11:30 बजे संसद भवन में संसदीय दल की बैठक बुलाई है। बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, "बहुमत दल के नेता के रूप में, हमारे पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमंत्री होंगे। सोमवार को बंगभवन स्थित राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने बताया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, बीएनपी सांसद अपने नेता का चुनाव करेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

समुद्र में अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

3 तेल टैंकर समुद्र से जब्त

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने मुंबई के पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। आईसीजी ने एक विशेष अभियान के तहत तेल और तेल आधारित माल से लदे तीन विदेशी जहाजों को रोका और जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि ये जहाज कथित तौर पर रूस और ईरान जैसे संघर्षग्रस्त देशों से सस्ता तेल प्राप्त कर रहे थे और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ही मोटर टैंकरों में उसका अवैध हस्तांतरण कर रहे थे। इस तरीके से तस्करी तटीय देशों द्वारा लगाए गए कड़े और शुल्क चूककर भारी मुनाफा कमा रहे थे। जब्त किए गए जहाजों की पहचान स्टेलर रूबी, एस्फाल्ट स्टार और अल जाफजिया के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, जहाजों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम और झंडे बदल लिए थे, लेकिन उनके आईएमओ नंबर पहले से अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जहाजों से मेल खाते थे। ईरान की राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी (एनआईओसी) ने इन जहाजों से किसी भी संबंध से इनकार किया है। आईसीजी का मानना है कि ये जहाज खुले समुद्र में अवैध तेल हस्तांतरण में शामिल थे और नियामक निगरानी से बच रहे थे। 5 फरवरी को, आईसीजी के जहाजों ने मुंबई से लगभग 100 समुद्री मील पश्चिम में तीन संदिग्ध जहाजों को रोका। एक विशेष



बोर्डिंग टीम ने गहन निरीक्षण किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम की जाँच, जहाज के दस्तावेजों का सत्यापन और चालक दल से पूछताछ शामिल थी। इस जाँच में तस्करी के पूरे तरीकों का खुलासा हुआ।

आईसीजी की प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली ने सबसे पहले भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर संदिग्ध रूप से संचालित एक मोटर टैंकर का पता लगाया। इसके बाद डिजिटल जांच और डेटा विश्लेषण के माध्यम से समुद्र में तेल आधारित माल के अवैध परिवहन में शामिल दो अन्य जहाजों की पहचान की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में चल रही अवैध तेल तस्करी पर कड़ी चोट लगी है और इसे तटीय सुरक्षा और नियामक अनुपालन के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।

शेख हसीना की वतन वापसी की अटकलें तेज, राहत भरी खबर सामने आई

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

बांग्लादेश की राजनीति में नए समीकरण तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की खबर पर मुहर लगते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में फिर मजबूती आ सकती है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भी बड़ा संकेत मिला है, जिसे उनकी संभावित वतन वापसी और बीएनपी के साथ राजनीतिक संवाद की दिशा में अहम माना जा रहा है। चुनाव नतीजों में बीएनपी की बढ़त के संकेत मिलते ही हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही बीएनपी से संपर्क साध सकती है। इसे जमात-ए-इस्लामी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वाजेद ने चेतावनी दी कि यदि जमात सत्ता में आती है या संसद में उसका प्रभाव बढ़ता है तो देश में आतंकवाद का खतरा फिर बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आवामी लीग भविष्य में मजबूती से वापसी करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान आवामी लीग की उस पुरानी रणनीति से अलग है, जिसमें बीएनपी को दशकों से कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता रहा है। हालांकि राजनीति में बदलते हालात के बीच नए गठजोड़ की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव के बाद आवामी लीग ने भी अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी हैं। खुलना में पार्टी कार्यालय दोबारा खोला गया है और नेताओं का आना-जाना शुरू हो गया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पार्टी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसे आम चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली थी। जुलाई विद्रोह के दौरान खुलना स्थित दफ्तर को जला दिया गया था, जिसे अब फिर से सक्रिय किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, आवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता देश लौटने की तैयारी में हैं और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल शेख हसीना भारत में हैं। उनकी संभावित वापसी पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि उनके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है।

का मानना है कि यह बयान आवामी लीग की उस पुरानी रणनीति से अलग है, जिसमें बीएनपी को दशकों से कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता रहा है। हालांकि राजनीति में बदलते हालात के बीच नए गठजोड़ की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव के बाद आवामी लीग ने भी अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी हैं। खुलना में पार्टी कार्यालय दोबारा खोला गया है और नेताओं का आना-जाना शुरू हो गया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पार्टी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसे आम चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली थी। जुलाई विद्रोह के दौरान खुलना स्थित दफ्तर को जला दिया गया था, जिसे अब फिर से सक्रिय किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, आवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता देश लौटने की तैयारी में हैं और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल शेख हसीना भारत में हैं। उनकी संभावित वापसी पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि उनके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है।

क्यों दिल्ली एआई समिट में बिल गेट्स की गैरमौजूदगी, एपस्टीन मामले से जुड़े विवादों ने बढ़ाई मुश्किलें?

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और अरबपति बिल गेट्स इस बार दिल्ली में चल रहे एआई शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। "ग्लोबल विज़नरीज" की सूची से उनका नाम हटाए जाने के बाद इस विषय पर अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण जेफरी एपस्टीन से जुड़े विवादित दस्तावेजों का सामने आना बताया जा रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट के आयोजकों ने अब गेट्स को प्रमुख वक्ताओं की सूची से हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक, विश्व के कई नेताओं और बड़े कारोबारियों के नाम एपस्टीन के कार्यालय से प्राप्त गोपनीय फाइलों में शामिल थे। जेफरी एपस्टीन अमेरिका के एक बदनाम फाइनेंस और बाल यौन शोषण के दोषी थे। उन्होंने अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में आत्महत्या कर ली थी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि एपस्टीन फाइलों में बिल गेट्स का नाम आने और इससे जुड़े विवाद के चलते उन्हें "अपरिहार्य कारणों" के चलते दिल्ली एआई शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। जनवरी में जारी की गई इन फाइलों में एपस्टीन ने गेट्स पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें दावा किया



गया था कि उनके बीच विवाहेतर संबंध रहे और गेट्स के साथ उनका रिश्ता "बिल को रूसी लड़कियों के साथ यौन संबंधों के परिणामों से निपटने के लिए ड्रग्स उपलब्ध कराने से लेकर विवाहित महिलाओं के साथ अवैध संबंधों में मदद करने तक फैला हुआ था।" यह मामला दुनिया भर में सुर्खियों में रहा और अरबपति परोपकारी के लिए विवाद का कारण बना। इस विवाद के बाद, बिल गेट्स ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। 4 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया की मीडिया हाउस 9News को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा, "मैं उन सभी क्षणों पर पछतावा करता हूँ

और इसके लिए माफी मांगता हूँ।" उनके इस बयान को निजी जीवन की गलती के रूप में पेश किया गया, लेकिन इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के चलते सम्मेलन में उनकी गैरमौजूदगी को उचित ठहराया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि गेट्स की गैरमौजूदगी एआई और तकनीकी जगत के लिए बड़ा अवसर नुकसान है, क्योंकि वह शिखर सम्मेलन के प्रमुख आकर्षणों में से एक माने जाते थे। वहीं, आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय निजी और सुरक्षा कारणों से लिया गया और सम्मेलन की मुख्य कार्यवाही पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।



संपादक की कलम से

मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की बैठक न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी महत्वपूर्ण संकेत देती है। यह मुलाकात दर्शाती है कि भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए गंभीर हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की और इसे विस्तार देने के अवसरों पर चर्चा की। वैश्विक चुनौतियों के सामने सहयोग की यह पहल दोनों देशों के लिए लाभकारी है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और बहुपक्षीय मंचों पर सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रतिबद्धता, भारत-फ्रांस रिश्तों में गहराई लाती है। मुंबई जैसे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र में हुई यह मुलाकात यह संदेश भी देती है कि रणनीतिक साझेदारी केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय तक टिकाऊ संबंधों की नींव रख सकता है। इस बैठक का महत्व केवल औपचारिक दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसा और विश्वास की भावना को भी मजबूत करता है। ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति अस्थिर है, भारत और फ्रांस का यह संवाद स्पष्ट संदेश देता है कि साझा हितों के लिए सहयोग ही स्थिरता का मार्ग है। मुंबई में हुई यह शिखर वार्ता दोनों देशों की दूरदर्शिता और रणनीतिक परिपक्वता का परिचायक है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इस साझेदारी का लाभ न केवल दोनों देशों को, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा को भी मिलेगा।

खारागे पैनल रिपोर्ट का खुलासा:

पुणे लैंड घोटेले में पार्थ पवार बरी, दो अधिकारियों पर कार्रवाई तय

पुणे भूमि सौदा मामले में लगभग 1,000 पृष्ठों की खारागे पैनल रिपोर्ट में पार्थ पवार को क्लीन चिट दी गई है। समिति ने हवेली रजिस्ट्रार कार्यालय के सब-रजिस्ट्रार रविंद्र तारु और तहसीलदार सूर्यकांत येओले के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। मामला मुंधवा की 44 एकड़ भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण से जुड़ा था।



टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पुणे में हुए विवादित भूमि सौदे में नई हलचल देखने को मिली है। इस मामले में कथित रूप से 1,800 करोड़ रुपये मूल्य की एक भूखंड को केवल 300 करोड़ रुपये में खरीदा जाने का आरोप लगा था। हाल ही में आई लगभग 1,000 पृष्ठों की सरकारी जांच रिपोर्ट ने इस घोटाले में पार्थ पवार को क्लीन चिट दे दी है, जबकि दो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट आईएस अधिकारी विकास शंकर खरागे की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई है। खरागे वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के पद पर तैनात हैं। समिति ने यह रिपोर्ट चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व वाले राजस्व विभाग को सौंप दी है, और इसे आगे के निर्देशों के लिए मुख्यमंत्री Devendra Fadnis के समक्ष रखे जाने की संभावना है। समिति को एमएस अमेडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी से जुड़े भूमि विक्रय मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इस फर्म के प्रमुख दिवंगत उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar के पुत्र पार्थ पवार हैं। पार्थ पवार की माता, Sunetra Pawar, वर्तमान में उपमुख्यमंत्री हैं और राज्य उत्पाद शुल्क, अल्पसंख्यक विकास, खेल एवं युवा मामलों के विभागों की प्रमुख हैं। यह विवाद मुंधवा स्थित 44 एकड़ भूमि के अवैध हस्तांतरण से

जुड़ा है। यह भूमि वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) को पट्टे पर दी गई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भूमि के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाली शीतल तेजवानी और पार्थ पवार के चचेरे भाई दिग्विजय पाटिल ने अभिलेखों में हेराफेरी कर भूमि का अवैध रूप से स्वामित्व अमेडिया एंटरप्राइजेज को हस्तांतरित किया। समिति ने इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की और पार्थ पवार को क्लीन चिट दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्थ पवार की ओर से कोई अनियमितता सामने नहीं आई, और वह भूमि सौदे में शामिल किसी भी अवैध गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। हालांकि, समिति ने हवेली रजिस्ट्रार कार्यालय के सब-रजिस्ट्रार रविंद्र तारु और तहसीलदार सूर्यकांत येओले के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। यह अधिकारी कथित तौर पर प्रक्रियात्मक चूक में शामिल पाए गए। समिति ने अपनी जांच में पाया कि भूमि के दस्तावेजों में कई त्रुटियां और अनियमितताएं थीं, जिनके कारण अवैध हस्तांतरण की संभावना बनी। इसमें अधिकारियों की लापरवाही और जिम्मेदारी के उल्लंघन को प्रमुख कारण बताया गया। समिति ने स्पष्ट किया कि पार्थ पवार किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं थे, बल्कि यह मामला कुछ अधिकारियों और भूमि के पूर्व मालिकों की कथित हेराफेरी का परिणाम था। इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पार्थ पवार

को क्लीन चिट मिलने के बाद राजनीतिक दलों में प्रतिक्रिया अलग-अलग रही। वहीं, दो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना के चलते प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यह कदम प्रशासन की निष्पक्षता और कानून के शासन को कायम रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुणे भूमि सौदा मामला महाराष्ट्र में राजनीतिक और प्रशासनिक सियासत में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। अब खरागे पैनल की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में एक नई दिशा सामने आई है। पार्थ पवार के क्लीन चिट मिलने के साथ ही मामले में अब केवल उन अधिकारियों पर कार्रवाई का फोकस रहेगा, जो कथित तौर पर प्रक्रियात्मक त्रुटियों और हेराफेरी में शामिल पाए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक जांच ने किसी भी राजनीतिक दबाव से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आगे अब मुख्यमंत्री के निर्देशों और राजस्व विभाग की कार्यवाही पर ही यह तय होगा कि दो अधिकारियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुणे भूमि सौदा मामले की कड़ी सियासी और प्रशासनिक निगरानी जारी रहेगी, और यह मामला महाराष्ट्र में सरकारी प्रशासन और राजनीतिक पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

नवजोत कौर का राहुल गांधी पर तीखा हमला: ‘आप इस कुर्सी के लायक नहीं’



टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कांग्रेस से निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू “बिक्री” तक के मामले सामने आए हैं और पार्टी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ हैं और उनके कथन व क्रांति से कमजोर किया जा रहा है, कर्म में बड़ा अंतर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पार्टी नेतृत्व ने समय रहते स्थिति नहीं सुधारी, तो 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। तैमिलनाडु के कोयंबटूर में भी आरोप लगाया कि उनसे और उनके पति, नवजोत कौर ने कहा कि राहुल गांधी वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू से किए गए समझौदारी भरी बातें तो करते हैं, लेकिन उन्हें वादे—जिनमें उपमुख्यमंत्री पद और लोकसभा अमल में नहीं लाते। एएनआई से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह पिछले आठ महीनों से गणू भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी के रुख पर उनसे मिलने का समय मांग रही थीं ताकि सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उनके पंजाब कांग्रेस में चल रही कथित आसपास के लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जबकि अनियमितताओं की जानकारी दे सकें। उनका

आरोप है कि राज्य इकाई में चुनाव टिकटों की अध्यक्ष सहित कई जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग न्याय नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस को अंदर से कमजोर किया जा रहा है, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। नवजोत कौर ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि उन्हें अपने अधीन हो रही गतिविधियों की जानकारी नहीं है, तो वे उस पद के योग्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनसे और उनके पति, नवजोत कौर ने कहा कि राहुल गांधी वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू से किए गए समझौदारी भरी बातें तो करते हैं, लेकिन उन्हें वादे—जिनमें उपमुख्यमंत्री पद और लोकसभा अमल में नहीं लाते। एएनआई से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह पिछले आठ महीनों से गणू भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी के रुख पर उनसे मिलने का समय मांग रही थीं ताकि सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उनके पंजाब कांग्रेस में चल रही कथित आसपास के लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जबकि अनियमितताओं की जानकारी दे सकें। उनका

AI पर PM Modi का मास्टरप्लान:

युवाओं के लिए Skill Development, Deepfake पर कसेगा शिकंजा

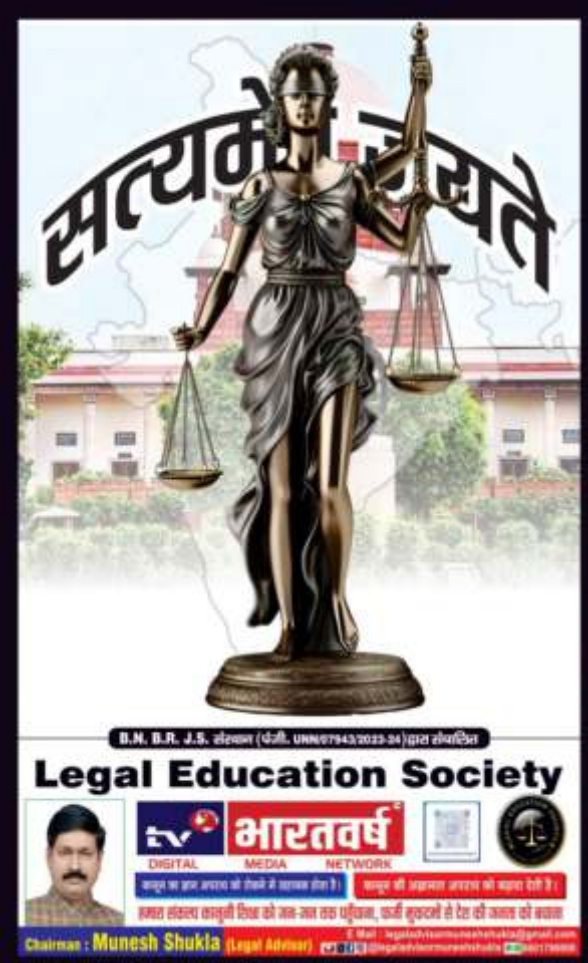
टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कप्रधानमंत्री मोदी ने भारत के युवाओं से जुड़ी बढ़ती चिंताओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा मानव नौकरियों के विस्थापन के मुद्दे पर ध्यान दिया है। एएनआई को दिए एक हालिया साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एआई मानव श्रम को समाप्त नहीं करेगा बल्कि उसे रूपांतरित करेगा। सरकार कौशल विकास और पुनर्कौशल विकास कार्यक्रमों में धन और प्रयास लगा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवा पेशेवर न केवल एआई-संचालित दुनिया में जीवित रहने के लिए बल्कि नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हों। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती अनुकूलन क्षमता के साथ, छात्र और युवा पेशेवर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एआई का उनकी नौकरी की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोदी ने पीढ़ियों के बीच इस घबराहट को भांप लिया है और उन्होंने एएनआई साक्षात्कार में कहा कि डर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका तैयारी करना है। उनका तात्पर्य यह था कि एआई को किसी खतरे के रूप में देखने के बजाय, उससे

निपटने के लिए तैयार रहें। सरकार एआई-संचालित भविष्य के लिए लोगों को कौशल प्रदान करने और उन्हें नए कौशल सिखाने में निवेश कर रही है। उन्होंने विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी कौशल विकास पहलों में से एक की शुरुआत की है। इसका अर्थ है कि भारत भविष्य की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। मोदी ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसरचना (डीपीआई) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का संगम समावेशी विकास की अगली सीमा है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का अनुभव वैश्विक दक्षिण के लिए व्यावहारिक सबक प्रदान करता है। एएनआई से विशेष बातचीत में, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का डिजिटल परिवर्तन अनुकरणीय सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें व्यक्तिगत हितों के बजाय जनहित और समावेश को प्राथमिकता दी गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसरचना की यात्रा वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सबक प्रदान करती है। डीपीआई और एआई



का संगम समावेशी विकास की अगली सीमा है। आधार, यूपीआई और अन्य डिजिटल सार्वजनिक सुविधाओं में हमारी सफलता आकस्मिक नहीं थी। यह कुछ अनुकरणीय सिद्धांतों से उपजी है। प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि भारत ने अपनी डिजिटल संरचना को एक जनहित के रूप में विकसित किया है।



एआई का बढ़ता प्रभाव: केवल आईटी नहीं, कई सेक्टर्स में बढ़ रही नौकरियों की मांग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने आज के रोजगार और उद्योग परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। बहुत से लोग मानते हैं कि एआई केवल आईटी सेक्टर को प्रभावित कर रहा है और वहीं इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असलियत इससे कहीं व्यापक है। एआई अब वित्त, हेल्थकेयर, मैनुफैक्चरिंग, रिटेल और लॉजिस्टिक्स जैसे कई सेक्टर में तेजी से अपनी पैठ बना रहा है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कुछ पारंपरिक नौकरियां खतरे में हैं, लेकिन इसके साथ ही नई नौकरी के अवसर भी खुल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, एआई की क्षमता सिर्फ डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सप्लाय चेन मैनेजमेंट जैसी जिम्मेदारियों में भी बढ़ रहा है। ऐसे में उन पेशेवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है जिनके पास एआई से जुड़े कौशल हों। वित्तीय क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल जोखिम प्रबंधन, फ्रॉड डिटेक्शन और इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स के लिए किया जा रहा है। बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां अब ऐसे पेशेवरों की तलाश में हैं जो डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन की मदद से बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकें। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल



रोगों के निदान, मेडिकल इमेजिंग, दवा और वैक्सीन विकास के लिए तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर और रिसर्चर अब एआई टूल्स की मदद से जल्दी और सटीक निदान कर सकते हैं, जिससे बायोइंफार्मेटिक्स और हेल्थ टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ रही है। मैनुफैक्चरिंग और उत्पादन क्षेत्रों में रोबोटिक्स और स्मार्ट ऑटोमेशन के जरिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इस सेक्टर में मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट और डेटा एनालिस्ट की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। रिटेल और ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहक व्यवहार और शॉपिंग

पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। पर्सनलाइजेशन, एनालिटिक्स और सप्लाय चेन ऑप्टिमाइजेशन में दक्ष पेशेवरों की मांग इस क्षेत्र में काफी बढ़ी है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाय चेन सेक्टर में एआई का इस्तेमाल ट्रैकिंग, डिमांड फोरकास्टिंग और डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जा रहा है। इसके चलते ऐसे पेशेवरों की जरूरत बढ़ रही है जो डेटा एनालिटिक्स और एआई टूल्स का कुशल उपयोग कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई से जुड़ी नौकरियों का विस्तार और तेज होगा। ऐसे में जो लोग समय रहते एआई की पढ़ाई और

प्रशिक्षण लेते हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर बहुत अधिक होंगे। कोडिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और रोबोटिक्स जैसी स्किल्स अब केवल आईटी पेशेवरों के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य सेक्टरों में भी बेहद महत्वपूर्ण बन गई हैं। यह साफ है कि एआई केवल एक तकनीकी ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह रोजगार और पेशेवर कौशल की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। जो लोग समय रहते इस बदलाव के अनुरूप अपने कौशल विकसित करेंगे, वे न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य के रोजगार बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे।

प्रमोद भगत ने विश्व चैंपियनशिप में जीता छठा स्वर्ण, अब नजर एशियाई खेल और लॉस एंजेलिस पैरालंपिक पर



डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण 2024 के पेरिस पैरालंपिक में नहीं खेल पाने वाले भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने हाल ही में विश्व खिताब जीतकर शानदार वापसी की है। विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) द्वारा 18 महीने के लिए प्रतिबंधित किए जाने के बाद भगत ने पैरा विश्व चैंपियनशिप में एसएल3 श्रेणी में अपना छठा एकल स्वर्ण पदक जीता और लगातार चौथा विश्व खिताब हासिल किया। 37 वर्षीय भगत ने फाइनल में इंडोनेशिया के मुहम्मद अल इमरान को 21-12, 21-18 से हराया। इस जीत ने उन्हें बैडमिंटन के इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाला पुरुष एकल विश्व चैंपियन बना दिया। उन्होंने कहा, “डेढ़ साल का प्रतिबंध मेरे लिए कठिन समय था, लेकिन वापसी के बाद विश्व चैंपियन बनना मेरे लिए भावनात्मक रूप से बेहद मायने रखता है।” भगत ने अपनी नजर अब जापान में होने वाले एशियाई खेल और 2028 में लॉस एंजेलिस पैरालंपिक पर टिकाई है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक और स्ट्रोक पर काम करेंगे और लगातार सुधार करते रहेंगे। एसएल3, एसएल4 और एसएल6 में भारत का दबदबा शानदार है और नए खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भगत का मानना है कि पैरा बैडमिंटन का भविष्य उज्ज्वल है।

शमी ने 8 विकेट की धमाकेदार पारी से सेलेक्टर्स को किया इम्प्रेस, टीम इंडिया में वापसी का किया दावा



वर्ल्ड कप हीरो वैभव सूर्यवंशी 10वीं बोर्ड परीक्षा देने नहीं पहुंचे क्या वजह IPL 2026 की तैयारी है?

न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 में बनाई जगह

न्यूजीलैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप के 31वें मुकाबले में कनाडा को 8 विकेट से हराकर सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली। चेन्नई के M. A. एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 4 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 15.1 ओवर में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 174 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को तीसरे विकेट के लिए ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र की शानदार साझेदारी ने जीत दिलाई। दोनों के बीच नाबाद 146 रन की साझेदारी हुई। फिलिप्स ने 36 गेंदों पर नाबाद 76 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने फिलिंडिंग में भी कमाल दिखाते हुए तीन कैच लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रचिन रवींद्र ने 39 गेंदों पर नाबाद 59 रन बनाए और फिलिप्स का बखूबी साथ निभाया। कनाडा की ओर से साद बिन जफर और

दिलोन हेलिगर को एक-एक विकेट मिला, लेकिन वे कीवी बल्लेबाजों को रोक नहीं सके। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए कनाडा के युवा बल्लेबाज युवराज समरा ने शानदार शतक जड़ा। 19 वर्षीय युवराज ने 65 गेंदों पर 110 रन बनाए और टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के Ahmed Shehzad (अहमद शहजाद) के नाम था, जिन्होंने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ 22 वर्ष 127 दिन की उम्र में शतक बनाया था। कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने 36 रन की पारी खेली। युवराज और दिलप्रीत के बीच पहले विकेट के लिए 116 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी, जैकब डफी, काइल जैमीसन और जिमी नीशम ने एक-एक विकेट हासिल किया। शानदार प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड ने मुकाबला जीतकर सुपर-8 में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली।

एफआईएच प्रो लीग 2026: हार्दिक सिंह को सौंपी गई कप्तानी हरमनप्रीत निजी कारणों से बाहर

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। नियमित कप्तान और स्टार ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह के निजी कारणों से हटने के बाद अनुभवी मिडफील्डर हार्दिक सिंह को आगामी एफआईएच प्रो लीग मैचों के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह टूर्नामेंट 20 से 25 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में खेला जाएगा। आगामी चरण में भारत, स्पेन और मेजबान ऑस्ट्रेलिया होबार्ट के तस्मानिया हॉकी सेंटर में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगे। भारतीय टीम राउरकेला में संपन्न पिछले चरण में अपने सभी चार मैच गंवा चुकी है। इसमें अर्जेंटीना के खिलाफ 0-8 की करारी हार भी शामिल रही, जिसने टीम के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। भारत के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने राउरकेला चरण के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा, “राउरकेला में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक

रहा और परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन हमने कुछ अच्छे सबक सीखे हैं और कुछ उल्लेखनीय सुधार किए हैं।” टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि होबार्ट में भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन कर वापसी करेगी। नए कप्तान हार्दिक सिंह दो बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हैं और टीम के अनुभवी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनकी अगुवाई में टीम संतुलन और आक्रामकता दोनों पर ध्यान देगी। हॉकी इंडिया ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि हरमनप्रीत सिंह निजी कारणों से इस चरण में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। सूत्रों के अनुसार, हरमनप्रीत अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण अपनी पत्नी अमनदीप कौर के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने टीम से हटने का निर्णय लिया। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिलेगा। अमनदीप लाकड़ा और मनमीत सिंह



जैसे युवा खिलाड़ियों ने राउरकेला चरण में सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया था और अब उन्हें एक और मौका मिला है। स्ट्राइकर मनिंदर सिंह की भी टीम में वापसी हुई है। वह आखिरी बार 2023-24 एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत के लिए खेले थे।

भारतीय प्रोफेशनल ने गिनाई खूबियां

जॉब के लिए नीदरलैंड्स पहली पसंद

30% टैक्स छूट, मजबूत लेबर लॉ और धानदार वर्क-लाइफ बैलेंस के कारण नीदरलैंड्स भारतीयों की पहली पसंद बन रहा है। सुरक्षित माहौल और भाषा की सुगमता इसे विदेश में नौकरी के लिए बेहतरीन विकल्प बनाती है।

भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए विदेश में नौकरी का सपना अब सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीय फाइनेंस प्रोफेशनल अनुज शर्मा की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने काम के लिए नीदरलैंड्स को क्यों चुना और यह फैसला उनके लिए कैसे बिल्कुल सही साबित हुआ। अनुज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया- मैंने किसी भी दूसरे देश की बजाय नीदरलैंड्स में काम करने



नीदरलैंड्स में 98 फीसदी लोग इंग्लिश बोलते हैं (Photo:Insta/@Anuj Sharma and Pixabay)

का फैसला क्यों किया। ये पोस्ट अब वायरल है। उनका कहना है कि ये वजहें उनके निजी अनुभवों पर आधारित हैं और हर किसी की परिस्थिति अलग हो सकती है। इसके बावजूद, इन 7 कारणों ने हजारों यूजर्स का ध्यान खींचा और पोस्ट

को खूब लाइक व शेयर मिला। नीदरलैंड्स में एक्सपैट्स के लिए 30% रूलिंग लागू है। यानी पहले 5 साल तक सैलरी का 30% हिस्सा टैक्स-फ्री। अनुज का कहना है कि इससे इन-हैंड सैलरी काफी बढ़ जाती है। अनुज के अनुसार, यहां

लेबर लॉ सख्त हैं और कर्मचारी अधिकार मजबूत हैं। इससे ऑफिस में सुरक्षा और स्थिरता महसूस होती है। करीब 98 फीसदी लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए नए लोगों को भाषा को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। ①



जापान में 30 मिनट के ओवरटाइम का भी मिलता है पूरा पैसा

जापान की काम करने की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। अब जापान में काम कर रही एक भारतीय शिक्षिका ने वहां के नियमों और काम के माहौल को लेकर ऐसा अनुभव शेयर किया है, जिसे जानकर लोग हैरान भी हैं और प्रभावित भी। उन्होंने बताया कि जापान में अतिरिक्त काम का पूरा पैसा मिलता है, चाहे वह सिर्फ 30 मिनट ही क्यों न हो। जापान अपनी अनुशासित और नियमों पर आधारित कार्य संस्कृति के लिए जाना जाता है। ②

बीमार मां की देखभाल के लिए मिली 1 महीने की पेड लीव

टारगेट से पहले इंसानियत ज़रूरी

आज के समय में ज्यादातर कंपनियों में कर्मचारियों से हर वक्त काम की उम्मीद की जाती है। ऐसे माहौल में एक भारतीय बिजनेस का इंसानियत भरा फैसला लोगों का दिल जीत रहा है। उन्होंने अपनी एक महिला

कर्मचारी को उसकी बीमार मां की देखभाल के लिए बिना किसी शर्त के पूरे एक महीने की पेड लीव दी। यह फैसला सोशल मीडिया ग्रोथ कंपनी बिंगलैब्स के सह-संस्थापक दिव्य अग्रवाल ने लिया। ③



पाकिस्तानी एक्ट्रेस के निकाह की क्लिप पर छिड़ी बहस

महीने के 5 लाख और शॉपिंग का खर्चा मांगा

सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान के एक निकाह समारोह का वीडियो जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो उसी वक्त चर्चा में आया जब यह बताया गया कि क्लिप पाकिस्तान की एक्ट्रेस हिना अफरीदी के निकाह की है।

हिना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर नैलेटिटी तैमूर अकबर से निकाह किया और शादी की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। लेकिन इन तमाम खूबसूरत पलों के बीच एक छोटी-सी वीडियो ने बहस छेड़ दी है। वायरल क्लिप में हिना अफरीदी बेहद हल्के-फुल्के अंदाज में अपने पति के सामने एक शर्त रखती नजर आती हैं। वीडियो में वह हंसते हुए कहती हैं कि उन्हें हर महीने 5 लाख रुपये, साथ ही ट्रेवल और शॉपिंग का पूरा



इंतज़ाम चाहिए। तैमूर अकबर भी मुस्कुराते हुए इन बातों से सहमत हो जाते हैं। देखने में यह पूरा संवाद मजाक-मस्ती जैसा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे दो बिल्कुल अलग नजरियों से लिया है और यही से बहस शुरू हुई। एक

तरफ कई यूजर्स का कहना है कि निकाह की रस्मों के दौरान हल्की-फुल्की नोकझोंक और मस्ती आम बात है। उनके मुताबिक, हिना ने जो कहा वह महज एक प्रतीकात्मक मजाक था, जिसे शादी के माहौल में गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। ④

सलमान खान के पिता सलीम खान ICU में,

4 डॉक्टरों की टीम कर रही देखरेख; सामने आया हेल्थ अपडेट

जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को 17 फरवरी की सुबह मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्हें हॉस्पिटल में क्यों भर्ती कराया गया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन उनके डॉक्टर ने आखिरकार सलीम खान की हेल्थ पर एक बयान दिया है। उन्होंने परिवार की प्राइव्सी का पूरा ख्याल करते हुए बताया कि उनका इलाज 4 अलग-अलग डॉक्टर्स की टीम कर रही है। उनके स्वास्थ्य पर और अधिक अपडेट देने के लिए एक हेल्थ बुलेटिन भी जल्द ही जारी किया जाएगा। सलीम खान का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने उनकी स्वास्थ्य को लेकर अपडेट साझा की है। उन्होंने हालिया बयान में कहा, 'सभी को नमस्ते! हां, यह

सच है कि मिस्टर सलीम खान (मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता) और जो खुद एक आइकॉन हैं, उन्हें सुबह 8.30 बजे लीलावती हॉस्पिटल के ICU में डॉ. जलील पारकर की देखरेख में भर्ती कराया गया है। उन्हें उनके फैमिली डॉक्टर डॉ. संदीप चोपड़ा इमरजेंसी में लाए थे। इमरजेंसी में इमरजेंसी केयर शुरू की गई और मिस्टर सलीम खान को पहली मंजिल पर इंटेंसिव केयर में शिफ्ट कर दिया गया। डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजीत मेनन (कार्डियोलॉजिस्ट), डॉ. नितिन डांगे (न्यूरोसर्जन) और डॉ. बिनीत अहलूवालिया की डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। सलीम खान की हेल्थ पर और अधिक जानकारी

साझा करते हुए डॉक्टर जलील ने कहा, 'रिश्तेदारों की रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए आज और जानकारी शेयर नहीं की जा रही है। हालांकि, कल सुबह 11 बजे हम रिश्तेदारों की सहमति से और मरीज की गोपनीयता को पूरी तरह बनाए रखते हुए एक प्रेस बुलेटिन देंगे। कृपया हमारा साथ दें। वह स्टेबल हैं लेकिन उनके क्लिनिकल स्टेटस के संबंध में उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सादर।' आज सुबह सलमान खान को लीलावती हॉस्पिटल के बाहर देखा गया। एक्टर को भारी सिक्योरिटी के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलते देखा गया। वह भीड़ से तेजी से निकले, बाहर इंतजार कर रही मीडिया को देखे बिना और सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। इसके बाद लगातार परिवार के लोग अस्पताल पहुंचते रहे। सलमा खान, हेलेन, अरबाज खान अपनी पत्नी शूरा खान के साथ और मलाइका-अरबाज के बेटे अरहान खान को लीलावती हॉस्पिटल पहुंचते हुए देखा गया। अलवीरा अग्निहोत्री भी हॉस्पिटल पहुंचीं। उनके पति अतुल अग्निहोत्री को भी सुबह अस्पताल के बाहर ही क्लिक किया गया। सलीम खान के दामाद और अर्पिता खान के पति आयुष शर्मा को भी लीलावती हॉस्पिटल में क्लिक किया गया।



लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े बैरिकेडिंग पर चढ़ाई सांसद समेत 300 कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट

लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता अजय राय और अन्य नेताओं के नेतृत्व में विधानसभा घेराव के लिए जुटे। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, कई बैरिकेडिंग पर चढ़े, 300 से अधिक को हाउस अरेस्ट किया गया और ईको गार्डन ले जाया गया।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में सोमवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर सधन सुरक्षा के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प देखने को मिली। यह घटनाक्रम तब हुआ जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अपनी नाराजगी जताने के लिए एकत्र हुए। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने मनरेगा, शंकराचार्य और माता अहिल्याबाई होल्कर के मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। इसे देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय और आसपास के इलाके को पहले ही कड़ी सुरक्षा में बदल दिया था। मौके पर आरएफ और पीएसी के 500 से अधिक जवान तैनात किए गए थे, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। घटना उस समय शुरू हुई जब लगभग 1000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर जमा हुए। कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और विधायक आराधना मिश्रा भी शामिल थे। पुलिस ने किसी तरह सभी को शांत करने और नियंत्रित करने का प्रयास किया। बताया गया है कि कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग से उतारने में पुलिसकर्मियों को काफी मशकत करनी पड़ी। आरएफ और पीएसी के जवानों ने कार्यकर्ताओं को



लखनऊ

ट्रकों में भरकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं को बस में टूस-टूसकर बिठाया गया और उन्हें ईको गार्डन तक पहुंचाया गया। इस दौरान अजय राय बैरिकेडिंग से उतरते समय लड़खड़ाए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभालकर किसी प्रकार की चोट लगने से बचा लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक घंटे तक इलाके में गहमागहमी का माहौल बना दिया। पुलिस प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती और यह सुनिश्चित किया कि किसी प्रकार की हिंसक घटना न हो। वहीं, इस प्रदर्शन को लेकर बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया समेत प्रदेशभर से आए करीब 300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये कार्यकर्ता लखनऊ के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोककर वापस भेज दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रशासन ने

विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया। पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच यह झड़प न केवल लखनऊ, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीतिक हलचल का हिस्सा बन गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मनरेगा, शंकराचार्य और माता अहिल्याबाई होल्कर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रदर्शन ने सरकार और विपक्ष के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। कांग्रेस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें लेकर विधानसभा पहुंचना चाहते थे। हालांकि सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने इस रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव हुआ। स्थानीय लोगों ने भी इस घटनाक्रम को देखा और कई ने इसे काफी तनावपूर्ण बताया। प्रशासन ने

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय किए, जिसमें कार्यकर्ताओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाना और बैरिकेडिंग से उतरने में मदद करना शामिल था। अंततः यह घटना राजनीतिक गतिविधियों के चलते हुई और इसे प्रदेश में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच जारी राजनीतिक टकराव के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन और पुलिस की सख्ती राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस तरह लखनऊ में सोमवार को कांग्रेस और पुलिस के बीच हुए इस टकराव ने पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरीं। कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सख्त थे, वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हर संभव कदम उठाया।

पत्नी से मिलने बुलाकर दामाद की हत्या की



टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में ससुराल आए दामाद की हत्या कर दी गई। विदाई के बहाने बुलाकर ससुर और सालों ने बेरहमी से पिटाई की। पेट और सीने में चाकू घोंप दिया। उपचार के उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके साथ आए भाई को भी चोट आई है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। घटना 16 फरवरी, सोमवार देर रात काकोरी थाना क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव में हुई। मृतक की पहचान रामसागर (24) के रूप में हुई। वह पीलीभीत जिले के माधव टांडा का रहने वाला था। उसने लालता खेड़ा गांव की रहने वाली कामिनी से 2 साल लव मैरिज की थी। इसका कामिनी के मायके वाले विरोध कर रहे थे। पीलीभीत जिले के माधव टांडा के रहने वाले रामसागर ने दिसंबर 2024 में कामिनी पुत्री भीमा गौतम निवासी ग्राम लालताखेड़ा थाना काकोरी से लव मैरिज की थी। दोनों ने घर से भागकर पहले पीलीभीत के एक मंदिर में शादी की थी। बाद में कोर्ट मैरिज कर ली थी।

इसके बाद दोनों पीलीभीत में रहने लगे थे। कुछ दिन बाद कामिनी के मायके वाले पीलीभीत गए। रामसागर और कामिनी की रीति-रिवाज से शादी कराने की बात की। इसके बाद कामिनी को लालताखेड़ा गांव ले गए। मृतक के भाई राहुल गौतम ने बताया- कामिनी को लालताखेड़ा लाने के बाद उसके मायके वालों ने उसे रामसागर को भूल जाने को कहा। उसे रामसागर से मिलने नहीं दिया। हालांकि, चोरी-छिपे कामिनी रामसागर से बात करती रही। इस बीच उसके मायके वालों ने उसकी दूसरी जगह शादी तय करनी चाही। कामिनी ने फोन करके इसकी जानकारी रामसागर को दी।

हार्ट एक्सपर्ट का चेतावनी: बच्चों की स्क्रीनिंग जरूरी लखनऊ में लेजर से होगा इलाज

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

सडेन कार्डियक डेथ के मामले बच्चों में दुर्लभ हैं, लेकिन इससे बचाव संभव है। इसके लिए विशेषज्ञों का कहना है कि फोकस स्क्रीनिंग पर होना चाहिए। खासकर उन परिवारों के बच्चों और करीबी सदस्यों की जांच जरूरी है, जिनके माता-पिता, भाई-बहन या दादा-दादी को युवा उम्र में सडेन कार्डियक डेथ का सामना करना पड़ा हो। KGMU के लारी कार्डियोलॉजी विभाग के फैकल्टी डॉ. प्रवेश विश्वकर्मा ने बताया कि स्क्रीनिंग से यह पता लगाया जा सकता है कि परिवार में कोई हार्ट की जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों में सांस फूलना, तेज धड़कन या पैरों में सूजन जैसी शिकायतों पर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसे बच्चों को एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। डॉ. प्रवेश ने बताया कि सडेन डेथ हमेशा हार्ट अटैक की वजह से नहीं होती, कभी-कभी ब्रेन संबंधी समस्याएं भी कारण बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कार्डियोलॉजी सोसाइटी की KGMU में हाल ही में हुई स्टेट कॉन्फ्रेंस में देशभर के करीब 200 हार्ट स्पेशलिस्ट ने इस बढ़ते खतरे पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने इस पर जोर दिया कि रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा फोकस स्क्रीनिंग और जीवनशैली सुधार पर होना चाहिए। लारी कार्डियोलॉजी विभाग में जल्द ही अत्याधुनिक लेजर तकनीक शुरू की जाएगी, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपए है। यह तकनीक दिल की बंद नसों को खोलने में मदद करेगी और कई मामलों में मेटल स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉ. ऋषि सेठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश का यह पहला सरकारी लेजर होगा। इसकी मदद से नसों में जमा



कैल्शियम की सख्त परत हटाना आसान होगा, जिससे भविष्य में ब्लॉकेज और जटिलताओं का खतरा कम होगा।

डॉ. सेठी ने कहा कि इस तकनीक से पहले से लगे गैर जरूरी स्टेंट को भी बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए निकाला जा सकता है। अनुमान है कि करीब 10-15% मरीजों को इससे विशेष लाभ मिलेगा। यह सुविधा लखनऊ में सरकारी और निजी संस्थानों में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे शुरू करना मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

लखनऊ में ATS अफसर बनकर दंपती से 90 लाख ठगे

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

एटीएस का जाल बिछाकर दंपती से 90 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दंपती को आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर बंधक बना लिया और 12 दिनों में आरटीजीएस के माध्यम से रकम ट्रांसफर करवा ली। गिरोह 3 प्रतिशत कमीशन पर फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराता था।

डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि 26 जनवरी 2026 को आलमबाग निवासी राकेश बाजपेई की पत्नी वीना बाजपेई के मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को एटीएस मुख्यालय का इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बताया। उन्होंने दंपती को आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाकर गिरफ्तारी की धमकी दी। इसके बाद सिमल एप डाउनलोड कराया गया और अजय प्रताप श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने भी खुद को एटीएस अधिकारी बताकर संपर्क किया। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश और सीजर दस्तावेज दिखाकर कहा कि खातों की जांच के लिए रुपए अलग खातों में



ट्रांसफर करना होगा। दबाव में आकर दंपती ने 29 जनवरी से 9 फरवरी के बीच अलग-अलग खातों में करीब 90 लाख रुपए भेज दिए। बाद में 11 लाख रुपए और मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान पिपराइच गोरखपुर निवासी मयंक श्रीवास्तव (24), निवाड़ी गाजियाबाद निवासी इरशाद (23) और प्रेम नगर मुंडका दिल्ली निवासी मनीष उर्फ आकाश (24) के रूप में हुई।

लखनऊ में वाहन चोर पकड़ा गया: चोरी की 6 बाइक और दो डाले बरामद

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ की मड़ियांव पुलिस ने शांति वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का दो डाला (छोटा हाथी) और उसमें लदी छह मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। आरोपी अलग-अलग थानाक्षेत्रों से बाइक चुराकर हरदोई ले जाकर बेच देता था। इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि सोमवार-मंगलवार की रात पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चारपहिया व दोपहिया वाहन चोरी करने वाला एक युवक यादव चौराहे से हरदोई रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर चोरी के गाड़ियों के साथ मौजूद है। सूचना पर टीम ने पुलिस बल को मौके पर बुलाया और घेराबंदी की। मुखबिर के इशारे पर सड़क किनारे तिरपाल से ढके खड़े एक डाले को घेरा गया। पुलिस को आता देख उसमें बैठा युवक भागने लगा लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान हरदोई निवासी अजीत शुक्ला उर्फ सुंदरम शुक्ला (20) के रूप में हुई। मौजूदा समय में फैजुल्लागंज लखनऊ रहता है। तलाशी में उसके पास से मोबाइल, आधार कार्ड और नकदी बरामद हुई।

लखनऊ नगर निगम की 57 इंडस्ट्री पर कुर्की की तैयारी: उद्यमियों का आरोप- गलत बिल भेजकर धमकी दे रहे अधिकारी

लखनऊ नगर निगम ने उन 57 इंडस्ट्री पर कुर्की की तैयारी शुरू कर दी है, जिन्होंने 2 करोड़ 35 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक जमा नहीं किया है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 507, 509 और 513 के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि पहले ही बकाएदार इंडस्ट्री मालिकों को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद टैक्स नहीं भरा गया। हाउस टैक्स न जमा करने की स्थिति में नगर निगम इंडस्ट्री की चल-अचल संपत्ति की नीलामी कर वसूली करेगा। इसमें चल संपत्ति जैसे मोटर कार, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, फर्नीचर और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले वसूली सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। साथ ही, नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि बकाएदार यदि बकाया टैक्स के साथ कुर्की चार्ज और अन्य शुल्क जमा कर देते हैं, तो उन्हें कुर्की की कार्रवाई से बचाया जाएगा। हालांकि, नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर लखनऊ के उद्यमियों

में नाराजगी है। उनका कहना है कि कई मामलों में नगर निगम ने गलत बिल भेजे हैं, जबकि कुर्की की धमकी दी जा रही है। उद्यमियों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी टैक्स नोटिस नियम के अनुसार नहीं भेज रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने लघु और सूक्ष्म उद्योगों को पहले ही टैक्स में राहत दी थी। इसके तहत छोटे उद्योग का टैक्स केवल आवासीय स्तर तक किया गया था। यह नियम सितंबर 2024 से लागू है। नगर निगम की नोटिस और कुर्की की तैयारी उन यूनिट्स के लिए है, जिन्होंने पहले बकाया टैक्स नहीं भरा। लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे तालकटोरा, चिनहट, सरोजनीनगर और नादरगंज में करीब 1500 इकाइयां हैं। इसके अलावा शहर में कुल 1,11,587 एमएसएमई इकाइयां हैं, जो प्रदेश में सबसे अधिक हैं। गाजियाबाद में यह संख्या 1,03,301 और कानपुर में 82,323 है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जोन-7 में कुल 63 बकाएदार यूनिट्स थीं, जिनमें से कुछ ने कुर्की नोटिस मिलने के बाद अपना बकाया टैक्स जमा कर दिया। लेकिन अभी भी करीब 57 यूनिट पर कुर्की की कार्रवाई की तैयारी है। इस कदम के बाद उम्मीद है कि बकाया टैक्स की वसूली में



तेजी आएगी, लेकिन उद्यमियों की नाराजगी और गलत बिल की शिकायतें प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई हैं।



प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के बटुकों की शिखा खींचने पर ब्रजेश पाठक ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

टीवी भारतवर्ष उत्तर प्रदेश

प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके बटुकों के साथ हुई घटना ने पूरे प्रदेश में चिंता और विवाद खड़ा कर दिया है। डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस घटना को महा अपराध बताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बटुकों की शिखा (चोटी) खींचना बिल्कुल गलत है और यह धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत सम्मान का अपमान है। ब्रजेश पाठक ने सख्त लहजे में कहा, “चोटी खींचना महा अपराध है। जिसने भी ऐसा किया होगा, उसे बहुत पाप पड़ेगा। प्रशासन को यदि बल प्रयोग करना था, तो लाठी या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए था, किसी की शिखा का अपमान नहीं होना चाहिए।” घटना मौनी अमावस्या के दिन हुई, जब शंकराचार्य स्नान के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने बताया कि भीड़ में अव्यवस्था से बचने के लिए उन्हें बिना पालकी के जाने के लिए कहा गया। लेकिन शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उन्हें अपमानित किया गया, उनके बटुकों की शिखा खींची गई और उन्हें मारने की साजिश रची गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि माघ मेले जैसे आयोजनों में चार करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसी जगहों पर जहां भगदड़ या अनुशासनहीनता की संभावना हो, वहां नियमों और मर्यादाओं का पालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा, “कानून का शासन लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। श्रद्धालुओं के जीवन और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले आचरण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।” विशेषज्ञों का कहना है कि माघ



मेले जैसी बड़ी धार्मिक घटनाओं में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सर्वोपरि है। आयोजकों और प्रशासन को संतुलन बनाए रखना होता है—सुरक्षा के साथ-साथ श्रद्धालुओं और धार्मिक नेताओं की गरिमा का भी सम्मान करना अनिवार्य है। इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि क्या भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के नाम पर धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान सुरक्षा में कई अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात थे। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन भीड़ और हालात के कारण कुछ अनुचित घटनाएं हुईं। ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ के बयानों ने साफ संदेश दिया है कि सरकार किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना ने न केवल प्रशासनिक सुधार और भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित किया है, बल्कि धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और अनुशासन के महत्व को भी उजागर किया है। धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा, अनुशासन और श्रद्धालुओं की गरिमा—तीनों का संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासनिक प्रोटोकॉल और धार्मिक भावनाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसी भी असावधानी

या अनुचित व्यवहार से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और सामाजिक अशांति की संभावना बढ़ सकती है। प्रयागराज माघ मेले की यह घटना इस बात का उदाहरण है कि बड़ी धार्मिक घटनाओं में व्यक्तिगत सम्मान और सुरक्षा को सर्वोपरि रखना कितना आवश्यक है। ब्रजेश पाठक और योगी सरकार के स्पष्ट बयानों ने यह संदेश दिया कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के अपमान या अनुचित व्यवहार को सरकार स्वीकार नहीं करेगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत ने प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत सम्मान का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सिद्धार्थनगर में बदनामी के डर से छात्रा ने दी जान,

टीवी भारतवर्ष सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जिले के शिवनगर डिंडई थाना क्षेत्र से एक विचलित करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग छात्रा ने प्रेमजाल, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधक के भतीजे ने छात्रा के आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर उसकी शादी तुड़वा दी थी, जिससे आहत होकर उसने सोमवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों के अनुसार, करमहिया गांव की रहने वाली इंटर की छात्रा क्षेत्र के ही एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ कॉलेज प्रबंधक के भतीजे शिखर शुक्ला ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोप है कि आरोपी पिछले डेढ़ साल से छात्रा का शारीरिक शोषण कर रहा था। इस दौरान उसने चोरी-छिपे छात्रा के आपत्तिजनक वीडियो बना लिए और कॉल रिकॉर्डिंग भी कर ली। इन वीडियो के दम पर वह छात्रा को लगातार डराने-धमाने लगा, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। बेटी की मानसिक स्थिति देख पिता ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। जब इसकी भनक आरोपी शिखर को लगी, तो उसने छात्रा के होने वाले ससुराल वालों को आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो क्लिप भेज दिए। इसके चलते छात्रा का रिश्ता टूट गया। इस घटना ने छात्रा को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया।

नशे की दवा पिलाकर लकवाग्रस्त व्यक्ति की 10 बीघा जमीन हड़पी,

टीवी भारतवर्ष कायमगंज

उत्तर प्रदेश के कायमगंज थाना क्षेत्र के अहमदगंज गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ दो दबंगों ने एक लाचार और मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को शराब और नशीली दवाओं के जाल में फंसाकर उसकी करोड़ों रुपये की 10 बीघा जमीन अपने नाम लिखवा ली। ताज्जुब की बात यह है कि इस सौदे के बदले पीड़ित को फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। पीड़ित सत्यभान ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 10 जुलाई 2025 को उनकी पत्नी कान्ती देवी के निधन के बाद वे गहरे मानसिक तनाव में थे। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर गांव के ही अनिल कुमार और आनंद त्रिपाठी ने उनसे मेल-जोल बढ़ाया। आरोप है कि सत्यभान को शराब की लत लगवाई गई और फिर उनकी शराब में गुपचुप तरीके से नशीली दवाएं मिलाई जाने लगीं। लगातार नशीली दवाओं के सेवन से सत्यभान की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें लकवा (पैरालिसिस) का दौरा पड़ गया। जब वे पूरी तरह बेबस हो गए, तो आरोपी उन्हें जबरन तहसील ले गए। वहां नशे की हालत में ही सत्यभान का अंगूठा लगवाकर जमीन का बैनामा वंदना त्रिपाठी और ब्रजेश कुमारी के नाम करवा लिया गया।

इटावा के जसवंतनगर में युवक ने घर में फांसी लगाकर दी जान

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

जसवंतनगर क्षेत्र के नगला खुमान गांव में मंगलवार सुबह एक 32 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी सूचना मिलते ही जसवंतनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया मामले की जांच शुरू कर दी गई है मृतक की पहचान अमन कुमार पुत्र राजकिशोर निवासी नगला खुमान के रूप में हुई है अमन पेशे से कंपाउंडर थे और इसी कार्य से परिवार का भरण पोषण करते थे सुबह जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आए तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा जहां वह फंदे से लटकें मिले यह दृश्य देखकर घर में चीख पुकार मच गई सूत्रों के अनुसार घटना से पहले अमन और उनकी पत्नी राखी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक तनाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया हालांकि पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी अमन अपने पीछे पत्नी राखी और चार वर्षीय पुत्र विहान को छोड़ गए हैं परिवार में उनकी मां सरोजा देवी बड़े भाई अवनीश और छोटे भाई कौशलेन्द्र भी हैं घटना के समय अधिकतर परिजन घर के बाहर मौजूद बताए जा रहे हैं थाना पुलिस के उपनिरीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है



धनंजय पर हमले में शामिल विधायक अभय के डॉक्टर-फार्मासिस्ट को कोर्ट ने तलब किया

टीवी भारतवर्ष वाराणसी

कैट थाना क्षेत्र के टकसाल सिनेमा के पास 24 साल पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। धनंजय सिंह पर हमले के आरोपियों में नामजद चार आरोपियों को गैंगस्टर केस में बरी किए जाने के बाद मुख्य मामले का ट्रायल तेज हो गया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से दाखिल धारा 311 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और बचाव पक्ष के प्ली ऑफ एलीबाई से जुड़े दो प्रमुख गवाहों को तलब किया है। इनमें डॉ. अरविंद कुमार सिंह और फार्मासिस्ट सुभाकर यादव शामिल हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होंगे। अभियोजन पक्ष का कहना है कि घटना के समय अभियुक्त अभय सिंह लखनऊ के एक सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उसी इलाज से जुड़े डॉक्टर और फार्मासिस्ट को बचाव पक्ष ने गवाह के रूप में पेश किया है। इससे पहले उनसे जरूरी तथ्यों पर पूछताछ नहीं हो सकी थी, जिसे अब दोबारा जिरह के जरिए किया जाएगा। वाराणसी एमपीएमएलए कोर्ट का यह केस शहर का सबसे पुराना और हाई-प्रोफाइल शूटआउट मामला माना जाता है। 2002 में दर्ज यह मामला वर्ष 2003 से सत्र न्यायालय में लंबित है। दोनों पक्षों के साक्ष्य वर्ष 2021 में पूरा हो चुके थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के चलते अंतिम फैसला लंबित रहा। एमपीएमएलए कोर्ट वाराणसी के जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने 24 साल पुराने नदेसर टकसाल सिनेमा शूटआउट केस की सुनवाई फिर से शुरू की है। अब कोर्ट ने मामले में नया मोड़ लाते हुए डॉक्टर और फार्मासिस्ट को

तलब किया है। आज की सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन गवाहों से जिरह करेंगे। अदालत ने साफ किया है कि यह मामला न्यायालय के सबसे पुराने लंबित मामलों में शामिल है, इसलिए साक्षियों की जिरह किसी भी स्थिति में टाली नहीं जाएगी। हालांकि अदालत ने मूल चिकित्सीय अभिलेख तलब करने की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन दोनों गवाहों की पुनः जिरह की अनुमति दे दी। बचाव पक्ष का दावा है कि घटना के समय अभियुक्त अभय सिंह और संदीप सिंह लखनऊ के सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। इसी आधार पर उन्होंने प्ली ऑफ एलीबाई (घटनास्थल पर मौजूद न होने का दावा) लिया था। अब इलाज से जुड़े डॉक्टर और फार्मासिस्ट से दोबारा जिरह कर इस दावे की सत्यता की पड़ताल की जाएगी। हाईकोर्ट ने इस केस में 6 नवंबर 2012 को निर्देश दिया था कि जब तक सत्र परीक्षण संख्या 461/2003 का निस्तारण नहीं होता, तब तक इस मामले में निर्णय न दिया जाए। 29 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकरण में बहस और जिरह की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकी है। करीब ढाई दशक पुराने इस हाई-प्रोफाइल शूटआउट केस में अब सुनवाई की रफ्तार तेज हो गई है। आज 17 फरवरी 2026 को होने वाली जिरह यह तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है कि प्ली ऑफ एलीबाई वास्तविक था या केवल बचाव की रणनीति। अदालत में होने वाली इस सुनवाई पर सभी पक्षों की नजर है, क्योंकि यह केस शहर और राज्य के राजनीतिक और कानूनी इतिहास में लंबे समय से चर्चा में है।



कानपुर में दिनदहाड़े 8 लाख की लूट

टीवी भारतवर्ष कानपुर

शहर के श्यामनगर क्षेत्र में दिनदहाड़े एक युवक से 8 लाख रुपए की लूट की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी। घटना श्यामनगर पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर शताब्दी उद्यान मोड़ के पास हुई। बताया गया कि चार बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर कट्टे के बट से हमला किया और उसका बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी और एडीसीपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस वारदात का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क किनारे कुछ बाइक सवार युवकों पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही आसपास लोग इकट्ठा होने लगे, बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए। हालांकि, बाद में पीड़ित ने इस लूट की घटना को झूठा बताया। श्यामनगर इलाके के रहने वाले मोहम्मद वासिद ने कहा कि बाइक टकराने के कारण चार लोगों ने उन्हें पीटा था। उन्होंने बताया कि जैसे ही आरोपी वहां से भागने लगे, उन्होंने लोगों को बताया कि लूट हुई है। वासिद ने स्पष्ट किया कि उनके साथ कोई लूट नहीं हुई और वे किसी कानूनी कार्रवाई की ओर नहीं बढ़ना चाहते। पीड़ित वासिद ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने गांव की जमीन बेची थी। सोमवार को उन्होंने करीब 8 लाख रुपए सिविल लाइन के बैंक से निकाले और बाइक से घर लौट रहे थे। उनके साथ उनका दोस्त अरसद भी था।

घटना के समय करीब 6 बजे से साढ़े 6 बजे के बीच दोनों युवक श्यामनगर पुलिस चौकी से शताब्दी उद्यान की ओर बाईपास की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने पेड़ के किनारे पेशाब करने के लिए बाइक रोकी। तभी पीछे से दो बाइकों पर सवार चार बदमाश आए। वासिद ने बताया कि उन्होंने विरोध किया, तो बदमाशों ने कट्टे के बट से उनके सिर पर हमला किया। जब वासिद लूट की घटना की जानकारी दे ही रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें अंदर की ओर ले लिया। बाद में जब पीड़ित अपने परिवार के

साथ बाहर निकले, तो उन्होंने और उनके परिवार ने भी लूट की बात से इनकार कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तीन बाइकों पर छह बदमाश आए थे। उन्होंने पहले दोनों युवकों को हेलमेट से पीटा और इसके बाद कट्टा निकाल लिया। इस दौरान आसपास के लोग उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि, वासिद ने अपने बयान में बदलाव करते हुए कहा कि यह पूरी घटना एक सड़क दुर्घटना और विवाद का परिणाम थी। उनके अनुसार दो बाइक सवार चार लोगों ने उन्हें मारा, जिससे उनके सिर में चोट आई। उन्होंने साफ किया कि उनके साथ कोई लूट नहीं हुई और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की कोई इच्छा नहीं जताई। उनके साथ मौजूद अरसद खान का इलाज फिलहाल उनके हेलमेट में जारी है। यह मामला कानपुर पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। शुरुआती सूचना और वीडियो देखकर इलाके में लोगों में भय और चौकन्नापन फैल गया था। लेकिन पीड़ित के बयान बदलने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह एक गंभीर लूट की घटना नहीं थी। पुलिस ने कहा कि अब वे घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सड़क पर हुई मारपीट और टक्कर किस तरह हुई। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट और वीडियो के आधार पर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और आसपास के CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में पीड़ित के बयान बदलना आम है, खासकर जब पुलिस हस्तक्षेप तत्काल होता है। कानपुर में इस मामले ने स्थानीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, श्यामनगर पुलिस चौकी के अधिकारी ने बताया कि घटना के वीडियो और स्थानीय लोगों के बयान का विश्लेषण किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध घटना या अपराध की जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो।

हरियाणा के आदेश से यूपी के 1.86 लाख शिक्षकों की बड़ी चिंता, टीईटी अनिवार्यता पर सियासत

हरियाणा के आदेश के बाद यूपी के 1.86 लाख बिना टीईटी पास शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल तक टीईटी अनिवार्य किया है। यूपी सरकार ने रिव्यू याचिका दाखिल की है, जबकि शिक्षक संगठन आंदोलन की तैयारी में हैं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

हरियाणा सरकार के हालिया आदेश ने उत्तर प्रदेश के 1.86 लाख ऐसे शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है, जिन्होंने अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास नहीं की है। हरियाणा सरकार ने 16 फरवरी को आदेश जारी कर कहा कि राज्य के शिक्षकों को मार्च 2027 तक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) पास करनी होगी। परीक्षा पास न करने वाले शिक्षकों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को इस मुद्दे की गुंज सुनाई दी। चित्रकूट से सपा विधायक अनिल प्रधान ने सरकार से पूछा कि जो शिक्षक TET पास नहीं हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। जवाब में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर जो निर्णय आया है, वह पूरे देश में लागू है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार इस मामले में रिव्यू याचिका दाखिल कर चुकी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को तमिलनाडु और महाराष्ट्र से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के



दौरान देशभर के जूनियर हाईस्कूल तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने का आदेश दिया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक का समय शेष है, उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना होगा। अन्यथा उन्हें इस्तीफा देना होगा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। साथ ही, राज्य सरकारों को दो वर्ष के भीतर सभी शिक्षकों को टीईटी पास कराने का निर्देश दिया गया। यूपी सहित कई राज्यों ने इस आदेश के खिलाफ रिव्यू याचिका दाखिल की है। यह याचिका फिलहाल उसी बेंच के पास लंबित है जिसने मूल आदेश दिया था। अन्य राज्यों की कुछ याचिकाओं में कमियां बताई गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद एक साथ सुनवाई की संभावना है। हालांकि, कई राज्यों की रिव्यू याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी की याचिका भी खारिज हो सकती है। यदि ऐसा हुआ, तो सरकार के सामने सितंबर 2027 तक टीईटी परीक्षा आयोजित कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद यूपी में शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ के जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रभाकांत ने बताया कि 22 से 24 फरवरी तक तीन दिन काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा। 26 फरवरी से हर जिले के बीएसए कार्यालय के बाहर धरना शुरू होगा। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रत्येक जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर के शिक्षक एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले 1.86 लाख शिक्षक ऐसे हैं, जो 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए थे और टीईटी

पास नहीं हैं। उनकी नियुक्ति बीएड, बीपीएड और बीटीसी के आधार पर हुई थी। इनमें कई इंटर पास और मृतक आश्रित शिक्षक भी शामिल हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) और एनसीटीई की 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के तहत पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है। शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से सेवा दे रहे हैं और सरकार उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण भी देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि राज्य के शिक्षक अनुभवी हैं और उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। शिक्षकों के दबाव में ही राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। इस मुद्दे पर भावनात्मक पहलू भी जुड़ गया है। हमीरपुर के 52 वर्षीय शिक्षक गणेशीलाल और महोबा के 49 वर्षीय शिक्षक मनोज कुमार की मृत्यु के बाद परिजनों ने दावा किया कि टीईटी

जन्म प्रमाणपत्र में देरी पर सपा का बहिष्कार, सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

यूपी विधानसभा में मंगलवार को जन्म और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने में आने वाली परेशानियों का आरोप लगाने पर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तकरार हो गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि एसआईआर में इन प्रमाण पत्रों को लगाने की अनिवार्यता होने की वजह से लोग इसे बनाने के लिए परेशान हैं, लेकिन एसडीएम इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच तकरार होने के चलते समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया।

संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विधायक रहने वाले हैं पश्चिमी यूपी के और मामला उठा रहे हैं पूर्वांचल का। शायद बॉर्डर पार कर नेपाल जाना चाहते हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनना चाहिए। इसका संज्ञान ले लिया गया है। कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि एसडीएम पुराने जन्म प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ऊपर से बनाने की मनाती है, तो इस पूरे मामले की जांच करा ली जाए। सपा सदस्य कमाल अख्तर ने जन्म-मृत्यु और निवास प्रमाण पत्र न बनाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सालों पुराने प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए उप जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी है। प्रदेश के अधिकतर जिलों से यह शिकायतें मिल रही हैं कि एसडीएम इसे बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद साक्ष्य के तौर पर इन प्रमाण पत्रों को मांगा जा रहा है और इसे बनवाने के लिए लोग परेशान घूम रहे हैं।

मनोज कुमार पारस ने कहा कि जन्म-मृत्यु, निवास, जाति या आय प्रमाण पत्र तहसीलों में नहीं बनाए जा रहे हैं। एसआईआर में इसे लगाने की अनिवार्यता की गई है। इसे न मिलने की वजह से मुस्लिमों का वोट काटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है।

बलिया के दफ्तर में दो महिला बीएलओ के बीच मारपीट, अधिकारियों के सामने हुआ हंगामा

टीवी भारतवर्ष बलिया

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। भृगु आश्रम स्थित कम्पोजिट स्कूल में सरकारी कामकाज के दौरान दो महिला कर्मचारियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मीटिंग का माहौल पूरी तरह अशांति में बदल गया। रिपोर्टों के अनुसार, यह बैठक SIR को लेकर आयोजित की गई थी, लेकिन देखते ही देखते बातचीत हाथापाई में बदल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है। वीडियो में दो महिला BLO आपस में बाल पकड़कर झगड़ रही हैं। कुछ देर तक जोर-जबरदस्ती और धक्का-मुक्की हुई, साथ ही मारपीट और लात-घूंसे तक चले। इस पूरी घटना ने सरकारी कामकाज के दौरान हिंसा और अनुशासनहीनता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में दलित महिला BLO सुमन देवी ने अपनी सहकर्मी नीलम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुमन देवी के अनुसार, उन्हें नोटिस वितरित करने के लिए बुलाया गया था और जब उन्हें अपेक्षित संख्या से ज्यादा नोटिस दिए गए तो



नीलम सिंह नाराज हो गई। आरोप है कि नीलम सिंह ने सुमन देवी को नीची जाति का कहकर अपमानित किया और जातिसूचक गालियां दीं। बहस बढ़ने पर नीलम सिंह ने सुमन देवी को बाल पकड़कर जमीन पर गिराया और घसीटा। सुमन देवी ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मामले में चुप्पी साधे हुए है। अब यह सवाल उठ रहा है कि सरकारी कामकाज के दौरान कर्मचारियों के बीच हिंसा और जातिगत अपमान की घटनाओं पर प्रशासन क्या कठोर कदम उठाएगा या इसे भी अनदेखा कर दिया जाएगा।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नौ छात्रों ने भारतीय तकनीकी कॉन्फ्रेंस

टीवी भारतवर्ष गोरखपुर

बेंगलुरु स्थित यू. आर. राव सैटेलाइट सेंटर, इसरो में 5-6 फरवरी 2025 को आयोजित अखिल भारतीय तकनीकी सम्मेलन में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग के नौ छात्रों ने अपने चयनित शोध पत्र प्रस्तुत किए। शोध छात्र आफताब अंसारी



और स्नातक छात्राएं अंकिता मौर्या, तन्वी राव, तान्या मिश्रा, तनु प्रिया त्रिपाठी, दिव्या शैलजा पांडे, विजय कुमार, प्रियांशु यादव और अमन मौर्या ने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों पर अपने शोध निष्कर्ष साझा किए। सम्मेलन में सभी प्रतिभागियों को यू. आर. राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा प्रमाण-पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही छात्रों को इसरो की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया, जिससे उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त हुई। छात्रों ने इस दौरान अंतरिक्ष-यात्री प्रशांत बालकृष्णन नायर और इसरो के वैज्ञानिकों से महत्वपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। इस तकनीकी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली सहित देश भर के छात्र और शोधार्थी सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश की ओर से गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रमुख प्रतिनिधित्व रहा और नौ छात्रों का चयन सबसे अधिक रहा। इस उपलब्धि ने विश्वविद्यालय के शोध और शैक्षणिक माहौल को उजगर किया। डॉ. राजेश कुमार, सहायक आचार्य और छात्रों के मार्गदर्शक, ने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलनों से छात्रों को न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में नई जानकारी मिलती है, बल्कि इसरो और डीआरडीओ जैसी संस्थाओं में करियर के अवसर भी स्पष्ट होते हैं। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी और कुलपति प्रो. पूनम टण्डन ने भी छात्रों की इस उपलब्धि की सराहना की और इसे विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शोध माहौल और विज्ञान प्रचार का प्रमाण बताया।

प्रति वर्ष 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन
गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में अग्रणी

करके दिखाए जो डबल इंजन सरकार है वो

UPGovtOfficial CMOUTtarpradesh CMOfficeUP

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश